

- (vi) In order to localise bad spots, a Pilot Scheme has been introduced on selected pairs of stations on different railways, which include transshipment points, where loading and unloading of affected commodities is closely supervised ;
- (vii) Plain clothes staff of R.P.F. are deployed to collect intelligence with a view to tracking down criminals ;
- (viii) Special detective staff are detailed to collect intelligence regarding receivers of stolen property and raids are organised on their shops/godowns with the assistance of Police ;
- (ix) Crime Intelligence staff of Railways and the Central Crime Bureau of the Railway Board are deployed to conduct surprise raids to effect red-handed arrests of the culprits ;
- (x) Close co-ordination between the R.P.F. and the Government Railway Police and the Local Police is maintained at various levels to deal effectively with the criminals and receivers of stolen property ;
- (xi) Special drives are conducted against the receivers of stolen property and cases are prosecuted under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1965.

इंजीनियरिंग उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग

164. श्री ईश्वर चौधरी :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री आर० वी० बड़े :

क्या आद्योगिक विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग एसोसियेशन के अध्यक्ष ने यह कहा है कि 500 करोड़ रुपये के मूल्य का अतिरिक्त उत्पादन

इंजीनियरिंग उद्योग की उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) दि इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने कहा था कि इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने की भी गुंजाइश है ।

(ख) उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने लाइसेंस नीति को उदार कर दिया है जिसके अनुसार ऐसे एकक जिनका विनियोजन 1 करोड़ रुपये से कम है कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस से मुक्त कर दिये गये हैं । सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उद्योगों की 'प्रतिबन्धित' सूची को भी समाप्त कर दिया है । सरकार आयात नीति को विशेषकर पूंजीगत सामान सम्बन्धी नीति को और भी उदार बना रही है / बनाने की सोच रही है ।

दोषपूर्ण मत पत्र

165. श्री ईश्वर चौधरी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में लोक सभा तथा कुछ राज्य विधान सभाओं के मध्यावधि चुनावों के सिलसिले में दोष-पूर्ण मत-पत्रों के स्थान पर कितने मत-पत्र छापने पड़े ;

(ख) उसका लेखा-जोखा रखने सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार दोष-पूर्ण